मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

बेलसोनिका 'ठेका मज़दूर' झेल रहे हैं भीषण शोषण 2
दहशत का माहौल पैदा करने वाले फैसले लेती है मोदी सरकार 4
दिल्ली पुलिस का बैड टच! 5
वायरल वीडियो में संघ के चाल-चरित्र पर चौंकाने वाले दावे 6
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल से 13 प्रोफेसरों का तबादला 8

वर्ष 37 | अंक 43 | फरीदाबाद | 28 मई-3 जून 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

रेडक्रॉस सोसायटी : पदाधिकारियों के संरक्षण में फल-फूल रहा भ्रष्टाचार

सोसायटी के क्लर्क ने 2020 में की साठ हजार रुपये की हेराफेरी, न हुई रिकवरी न दर्ज कराया गया केस

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जिला रेडक्रॉस सोसायटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। यहां कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है और अधिकारी उस पर पर्दा डालते हैं। यहां तक कि ऑडिट में वित्तीय अनियमितता पकड़े जाने के बावजूद अधिकारी दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे जबकि स्टेट हेड क्वार्टर भी कई बार आदेश जारी कर चुका है।

रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से 18 व 19 दिसंबर 2020 को एक दिवसीय बेसिक ट्रेनिंग कराई गई थीं। ट्रेनिंग में अभ्यर्थियों से शुल्क आदि वसूली का जिम्मा रेडक्रॉस सोसायटी के तत्कालीन लिपिक जतिन शर्मा को सौंपा गया था। इसके लिए उसे सोसायटी की ओर से रसीद बुक संख्या 11101-11200 और 11301-11400 दी गई थीं। जतिन ने प्रत्येक रसीद बुक पर तीस हजार रुपये यानी कुल साठ हजार रुपये वसूले। उसने यह रकम न तो सोसायटी के खाते में जमा की और न ही अकाउंट बुक में दर्ज कराई। यह संभव नहीं कि अधिकारियों को रकम जमा नहीं कराए जाने की जानकारी न हो लेकिन किसी

जतिन शर्मा

ने जतिन से न तो रसीदों के बारे में पूछा और न ही वसूली गई रकम का ब्यौरा मांगा।

साठ हजार रुपये की यह हेराफेरी खुलती भी नहीं, लेकिन मार्च 2021 में ऑडिट टीम ने इसे पकड़ा।

ऑडिटर विजय कुमार ने जतिन शर्मा की साठ हजार रुपये की हेराफेरी पकड़ी और इसकी रिपोर्ट जिला स्तरीय अधिकारियों से लेकर राज्य मुख्यालय को भेजकर, रकम वसूले जाने की सिफारिश की। मार्च 2021 में राज्य मुख्यालय की ओर से जिला मुख्यालय को पत्र लिखा गया जबकि 8 अप्रैल 2021 को जतिन को भी पत्र लिख कर रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया।

आडिट रिपोर्ट आए दो साल से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन किसी अधिकारी ने जतिन से रुपये जमा करवाने का प्रयास नहीं किया। जतिन पर अभी साठ हजार रुपये का बकाया था बावजूद इसके उसका तबादला गुड़गांव कर दिया गया। यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव है कि जतिन से बिना उसके ड्यूज क्लियर कराए उसे रिलीव कर दिया गया, ताकि गुड़गांवा जा कर नए सिरे से लूट खसोट कर सके।

बताते चलें कि कोरोना काल के दौरान रेडक्रॉस सोसायटी में हुए ऑक्सीजन घोटाले की तीन आरोपियों में जतिन शर्मा एक है। बाकी दो आरोपी तत्कालीन सचिव विकास और आजीवन सदस्य विमल खंडेलवाल हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी का भ्रष्ट आचरण साबित होने पर नियमानुसार रिकवरी के अलावा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी, अमानत में खयानत आदि धाराओं में केस दर्ज कराया जाना चाहिए।

इस संबंध में रेड क्रॉस सोसायटी के जिला सचिव विजेंद्र सौरोत से उनके फोन नंबर 9812974627 पर बार-बार पूछने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने हर बार फोन काट दिया। जाहिर है कि वे खुद भी इस घोटाले में शामिल होने की वजह से कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं।

संघ एवं भाजपा कोष में वृद्धि का बड़ा स्रोत है लूट कमाई

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तवार की लूट कमाई का एक बड़ा किस्सा आजकल बड़ी चर्चा में है। दस्तावेजों के साथ बताया जा रहा है कि किस तरह से नौ एकड़ जमीन की खरीदो फरोख्त से एक झटके में पचासों करोड़ रुपये की लूट कमाई कर ली गई। इसके अलावा खट्टर के दूसरे ओएसडी जवाहर यादव की लूट कमाई के अनेकों किस्से चर्चा में हैं। सवाल उठने पर खट्टर ने इनका कोई जवाब देने की अपेक्षा अपने इन दोनों कलेक्शन एजेंटों को चुपचाप उनके पदों से फ़ारिग़ कर दिया।

नीरज दफ्तवार तथा जवाहर तो सीएम सेल के प्रमुख कलेक्शन एजेंट समझे जाते रहे हैं। इन दोनों के अलावा अनेकों और भी कलेक्शन एजेंट इनके दफ्तर तैनात हैं। इतना ही नहीं हर जिले में इस तरह के कलेक्शन एजेंट तैनात किए हुए हैं जैसे कि फरीदाबाद में अजय गौड़, यूं भाजपाई सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से भी जमकर लूट कमाई करती आ रही है जिसमें से अच्छा खासा हिस्सा

शेष पांच पर

भ्रष्टाचार रोकने का नया ढिंढोरा

अब भ्रष्ट अधिकारी ही फ्लाईंग स्कवाड बनकर भ्रष्टों को पकड़ने का करेंगे ड्रामा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भ्रष्टाचार को खत्म मत करो, भ्रष्टाचार को खत्म करने का ढिंढोरा पीटो की तर्ज पर अब खट्टर सरकार स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार खत्म करने का नाटक कर रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए विजिलेंस और सीएम लाइंग स्क्वाड जैसे कम पड़ रहे थे जो 22 शहरी स्थानीय निकायों में भी फ्लाइंग स्क्वाड का गठन करना पड़ा। कारण बताया गया कि यह स्क्वाड जांच और पूछताछ के जरिए विभाग और सरकार की धूमिल हो रही छवि को संवारेगी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपनी जिला स्तरीय इकाइयों में भ्रष्टाचार, निगम की जमीनों पर कब्जा, अवैध विज्ञापन, अतिक्रमण, प्रॉपर्टी टैक्स, विकास कार्यों में गड़बड़ी, अवैध निर्माण आदि की शिकायतों की जांच और पूछताछ के लिए 22 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए हैं।

स्कवाड का इंचार्ज किसी नगर निकाय के एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल काउंसिल, चीफ इंजीनियर पद पर बैठे लोगों को बनाया गया है। यह फ्लाइंग

कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

स्कवाड किस जिले के नगर निगम, नगर निकाय की जांच और पूछताछ करेंगे यह भी निर्धारित कर दिया गया है यानी एक चोर के विरुद्ध आई शिकायत की जांच दूसरा चोर करेगा।

प्रदेश के सभी नगर निगम-निकायों में भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं। रोजाना भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण, घटिया विकास कार्यों की शिकायतें आती रहती हैं। इन निकायों में तैनात यही अधिकारी न तो उन शिकायतों की जांच करते, करवाते हैं और न ही भ्रष्टाचार को रोकने के कोई ठोस उपाय करते हैं। ऐसे में इनको फ्लाइंग स्कवाड का प्रभारी बनाना शोशेबाजी से ज्यादा कुछ नही है, यदि नीयत सही होती तो यह अधिकारी भ्रष्टाचार होने ही नहीं देते, घटिया काम करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करते। लेकिन अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी तो लूट कमाई में इनका हिस्सा नहीं बनेगा। फरीदाबाद में ही एक आरटीआई कार्यकर्ता अवैध होर्डिंगों के खिलाफ निगम अधिकारियों को न जाने कितनी शिकायतें दे चुका है। मुख्यमंत्री से भी शिकायत के बावजूद निकम्मे अधिकारियों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कैसे मान लिया जाए कि फ्लाइंग स्क्वाड बनने से यह अधिकारी काम करने लगेंगे।

जानकार लोगों का कहना है कि निगमों में फैले भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस या कोई और विभाग न कर सके इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड का ड्रामा रचा गया है। यानी विभाग की बात विभाग में ही रह जाए। आने वाली शिकायतों का नगर निकाय के अधिकारी अपनी तरह जांच कर एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालने का काम करेंगे।

जाहिर सी बात है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। सरकार और विभाग के लोग इस बात पर अपनी पीठ ठोकेंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का बड़ा काम कर दिया है जबकि आम जनता भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों के चक्कर लगाती रहेगी, सारा मतलब जनता की आखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है।